Drishti IAS

करेंट अफेयर्स बिहार

मई 2023

(संग्रह)

Drishti, 641, First Floor, Dr. Mukharjee Nagar, Delhi-110009
Inquiry (English): 8010440440, Inquiry (Hindi): 8750187501
Email: help@groupdrishti.in

अनुक्रम

बिहार 3

- अरविंद पनगढ़िया बने नालंदा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति 3
- पहली बार मछली उत्पादन में आत्मनिर्भर हुआ बिहार, 8.46 लाख टन हुआ उत्पादन 3
- आईआईटी पटना और सी-डैक के मध्य हुआ एमओयू साइन 3
- आईजीआईएमएस और सी-डेक के मध्य एमओयू 4
- मिशन परिवर्तन 4
- भारत-नेपाल के बीच बथनाहा से एनसीवाई तक जल्द दौड़ेगी ट्रेन 5
- विश्व रिकॉर्ड में दर्ज पटना की गंगा महाआरती 5
- बिहार में धान के नई किस्म सबौर कुंवर की खोज 6
- डॉ. देवेंद्र कुमार शुक्ला बने बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नए अध्यक्ष 6
- मध्य प्रदेश की तर्ज पर बिहार में भी ज़मीन की रजिस्ट्री में अब आधार अनिवार्य 6
- बिहार के सारण में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन 7
- मजदूर के बेटे का कैलिफोर्निया में 2023 हैनसेन लीडरशिप प्रोग्राम के लिये चयन 7
- बिहार में गंगा नदी के किनारे वाले शहरों में बनेगा एसटीपी 8
- बिहार रजिस्ट्रीकरण नियमावली-2023 अधिसूचित 9
- देश में CBDC का इस्तेमाल करने वाला पहला नगर निगम बना पटना 9
- बिहार के हर पंचायत में लगेंगी फूड प्रोसेसिंग यूनिट 9
- बिहार के समीर पांडे ऑस्ट्रेलिया में मेयर पद हासिल करने वाले पहले भारतीय बने 10
- 'नेशनल वाटर अवार्ड 2022' में तीसरे स्थान पर रहा बिहार 10
- बिहार में 793.97 करोड़ रुपए के 67 निवेश प्रस्तावों को मिली पहली मंजूरी 11
- बिहार शिक्षा विभाग और चार NGO के मध्य होगा एमओयू 12
- बिहार के सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों के भवन एक ही रंग के होंगे 12

नोट :

बिहार

अरविंद पनगढ़िया बने नालंदा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति

चर्चा में क्यों ?

29 अप्रैल, 2023 को भारत सरकार द्वारा प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अरविंद पनगढ़िया को बिहार के नालंदा ज़िले में स्थित प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया है।

प्रमुख बिंदु

- नवनियुक्त कुलाधिपति अरविंद पनगढ़िया वर्ष 2015 में स्थापित नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष के रूप में कार्य कर चुके हैं।
- पद्मभूषण से सम्मानित अरविंद पनगढ़िया वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका की सम्मानित कोलंबिया यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं।
- उल्लेखनीय है कि बिहार के नालंदा ज़िले में स्थित प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के परिसर में ही नवस्थापित नालंदा विश्वविद्यालय भारतीय संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित राष्ट्रीय महत्त्व का एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है, जो विदेश मंत्रालय के तत्वावधान में कार्य करता है।

पहली बार मछली उत्पादन में आत्मनिर्भर हुआ बिहार, 8.46 लाख टन हुआ उत्पादन

चर्चा में क्यों ?

2 मई, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में वर्ष 2022-23 में कुल मछली उत्पादन 8 लाख 46 हज़ार टन हुआ। 2021-22 में 7.61 लाख टन की तुलना में यह 85 हज़ार टन अधिक है।

प्रमुख बिंदु

- उल्लेखनीय है कि बिहार में सालाना 8.02 लाख टन मछली की ज़रूरत रहती है।
- बिहार पशु व मत्स्य संसाधन विभाग ने मछली उत्पादन का आँकड़ा तैयार किया है, जिसके अंतर्गत मधुबनी में सबसे अधिक 88.96 हज़ार टन, जबकि जहानाबाद में सबसे कम 1.55 हज़ार टन उत्पादन हुआ है।

नोट :

- पहली बार बिहार ने ज़रूरत से अधिक मछली का उत्पादन कर लिया है। अभी तक राज्य में मछली की ज़रूरत को पूरा करने के लिये लगभग 800 करोड़ की मछली आंध्र प्रदेश एवं राज्यों से मंगाना पड़ता था।
- अब उत्पादन अधिक होने से मत्स्य व्यापारी दूसरे राज्यों में अधिक मछली भेजने में भी सफल होंगे।
- उल्लेखनीय है कि बिहार से मछली का निर्यात पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल और नेपाल भी किया जाता है।

आईआईटी पटना और सी-डैक के मध्य हुआ एमओयू साइन

चर्चा में क्यों ?

02 मई, 2023 को आईआईटी पटना में सितंबर 2023 तक सुपर कंप्यूटर स्थापित करने के लिये आईआईटी पटना और सी-डैक के बीच एमओयू साइन हुआ है।

प्रमुख बिंदु

- इस एमओयू पर आईआईटी पटना के निदेशक प्रो. टी एन सिंह और सी-डैक के महानिदेशक (डीजी) ई. मगेश ने हस्ताक्षर किया।
- नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत इस वर्ष सितंबर तक आईआईटी सुपर कंप्यूटर पावर से लैस हो जाएगा। इस सुपर कंप्यूटर को लगाने की लागत 20 करोड़ रुपये होगी।
- इस सुपर कंप्यूटर से 833 टेरा फ्लॉप या एक ट्रीलियन फ्लोटिन प्वाइंट ऑपरेशन के साथ डेटा की गणना कर सकते हैं।
- उल्लेखनीय है कि केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ओर से देश के नौ संस्थानों में आईआईटी पटना का चयन किया गया है।
- यह सुपर कंप्यूटर एक मील का पत्थर साबित होगा और यह विभिन्न उद्देश्यों के लिये उच्च स्तर की डेटा गणना को बढ़ाएगा।
- इसके द्वारा मौसम का पूर्वानुमान लगाने में मदद मिलेगी साथ ही इससे कृषि से लेकर बाढ़ की आशंका पर अलर्ट जारी किया जा सकेगा।
- उद्यमिता के क्षेत्र में कार्यरत युवाओं को इससे बहुत लाभ मिलेगा।
- सुपर कंप्यूटर आने से आर्टिफिशियल इंटीलिजेंस, बिग डेटा, सिक्योरिटी, क्वांटम सिमुलेशन, प्रोसेस सिमुलेशन एंड ऑप्टिमाइजेशन, कंप्यूटेशनल फ्यो डायनामिक्स, वेदर मॉडलिंग, डिजास्टर रिकवरी, ड्रग डिस्कवरी, मॉलिक्यूलर डायनेमिक्स, मशीन लर्निंग सहित विभिन्न क्षेत्रों में काम हो सकेगा।
- गौरतलब है कि इसका बुनियादी ढाँचा रुद्र सर्वर पर आधारित है, जिसे भारत में स्वदेशी रूप से डिजाइन, निर्मित और असेंबल किया गया है। यह आत्मनिर्भर भारत की ओर एक कदम है।

नोट :

आईजीआईएमएस और सी-डेक के मध्य एमओयू

चर्चा में क्यों ?

02 मई 2023 को बिहार के पटना में इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस (IGIMS) संस्थान और विकास संगठन सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग (C-DAC) ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक एमओयू साइन किया गया।

प्रमुख बिंदु

- इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस संस्थान के निदेशक डॉ विनय कुमार, C-DAC पटना के निदेशक आदित्य कुमार सिन्हा और C-DAC के महानिदेशक ई मंगेश के उपस्थिति में एमओयू पर साइन कर किये गए।
- इस एमओयू के होने से अब पटना शहर के इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस (IGIMS) संस्थान में मशीन और सॉफ्टवेयर का उपयोग कर, डॉक्टर मरीजों का बेहतर इलाज करेंगे। बेहतर इलाज के लिये अब यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल किया जाएगा।
- अब दोनों संस्थान मिलकर कैंसर सहित कई घातक रोगों और औषधियों के विकास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल करेंगे और मरीजों का इलाज करेंगे।
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रयोग से स्वास्थ्य क्षेत्र में मेडिकल डाटाबेस तैयार करने,उपकरण के रखरखाव, स्टाफ की कमी दूर करने और प्रयोगशाला सुविधाओं को बढ़ाने तथा रोगों का शीघ्र पता लगाने और इसके निदान आदि में काफी मदद मिलेगी। यह मरीज और संस्थान दोनों के लिये काफी लाभप्रद साबित होगा।
- उल्लेखनीय है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा तकनीकी सिस्टम होता है जिसमें सॉफ्टवेयर के जरिये कंप्यूटर को इंसानों की तरह सोचने, समझने, काम करने और प्रतिक्रिया देने की क्षमता विकसित की जाती है।यह आर्टिफिशियल तरीके से सोचने, समझने और सीखने की क्षमता रखता है।

मिशन परिवर्तन

चर्चा में क्यों ?

4 मई, 2023 को बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों की सेहत में सुधार के लिये मिशन 60 दिन के तर्ज पर मिशन परिवर्तन लॉन्च किया।

प्रमुख बिंदु

- इस मिशन का मुख्य उद्देश्य अस्पतालों को मरीज फ्रेंडली बनाना, कॉलेजों में अनुशासन को लागू करने के साथ ही मैनपावर के आधार पर इलाज की व्यवस्था करना है।
- इसके अलावा मेडिकल कॉलेज, अस्पतालों में साफ-सफाई, मरीजों व परिजनों के बैठने के लिये प्रतीक्षालय, साइनेज को लगाना, 'मे आई हेल्प यू'डेस्क स्थापित करना भी इस मिशन के लक्ष्य हैं।
- मिशन की लॉचिंग के साथ ही मेडिकल कॉलेजों में इलाज को टास्क दिया है कि जिस कॉलेज में जितना मानव बल है, उसका भरपूर उपयोग करें।
- मेडिकल कॉलेजों की बेसिक सुविधा में सुधार कर परफॉर्मेंस दिखाना होगा। 1 माह में मेडिकल कॉलेजों की फिर से समीक्षा की जाएगी, जिससे यह आकलन किया जा सके कि कार्यशैली, व्यवस्था और इलाज की दिशा में कितना बदलाव दिख रहा है।
- उप-मुख्यमंत्री ने कॉलेजों को निर्देश दिया है कि प्रत्येक दिन इवनिंग राउंड सुनिश्चित किया जाए और कम से कम असिस्टेंट प्रोफेसर स्तर के डॉक्टर द्वारा वार्ड में राउंड लगाया जाए।
- सभी मेडिकल कॉलेजों में 611 प्रकार की आवश्यक दवाओं उपलब्ध रहें, जिससे मरीजों के पॉकेट पर बोझ कम हो।

नोट :

भारत-नेपाल के बीच बथनाहा से एनसीवाई तक जल्द दौड़ेगी ट्रेन

चर्चा में क्यों ?

7 मई, 2023 को रेलवे बोर्ड के कार्यपालक निदेशक ट्रैफिक ट्रांसपोर्ट प्रदीप कुमार ओझा ने बताया कि बिहार के अररिया ज़िले के जोगबनी-विराटनगर क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक के तहत भारत-नेपाल के बीच बथनाहा से जोगबनी नेपाल कस्टम यार्ड तक निर्मित रेललाइन पर जल्द ही ट्रेन का संचालन शुरू किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- उल्लेखनीय है कि नेपाल के काठमांडू में विदेश मंत्रालय के आठवी प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमेटी (पीएससी) व छठा ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई थी, जिसमें बथनाहा व नेपाल कस्टम यार्ड के बीच कार्गो ट्रेन मई 2023 से शुरू करने का निर्णय लिया गया था।
- भारत और नेपाल को जोड़ने वाली महत्त्वपूर्ण रेल परियोजना जोगबनी-विराटनगर क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक प्रोजेक्ट के तहत बथनाहा से विराटनगर तक रेललाइन निर्माण का कार्य इरकॉन कंपनी के द्वारा किया गया।
- रेल लाइन निर्माण कार्य में लगी इरकॉन के द्वारा बथनाहा से नेपाल कस्टम यार्ड तक के कार्य को पूरा कर लिया गया है।

विश्व रिकॉर्ड में दर्ज पटना की गंगा महाआरती

चर्चा में क्यों ?

7 मई, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार आईडीपीटीएस की ओर से पटना के कलेक्ट्रेट घाट पर आयोजित 11 दिवसीय गंगोत्सव का कार्यक्रम गंगा महाआरती के अद्भुत प्रदर्शन के साथ संपन्न हुआ। यह कार्यक्रम वर्ल्ड रिकार्ड में दर्ज किया गया।

प्रमुख बिंदु

- इस ऐतिहासिक गंगा आरती का संगीत संयोजन व निर्देशन बक्सर की धरती के लाल मुरार ग्राम के कथक गुरु बख्शी विकास ने किया।
- विदित है कि कार्यक्रम का आयोजन 27 अप्रैल 2023 को कलेक्ट्रेट गंगा घाट पर शुरू हुआ था। इसमें 501 महिलाओं ने नृत्य के माध्यम से गंगा महाआरती की।
- इस आरती का संगीत अवधी, हिन्दी, संस्कृत व रशियन भाषा से सजाया गया था। वहीं, भारत की सप्त नदियों के पौराणिक, आध्यात्मिक और भौगोलिक पक्ष का दिव्य दर्शन आरती के माध्यम से दर्शकों तक सुगमता से पहुँचाया गया।
- गंगोत्सव में कथक नृत्यांगना सह गुरु आदित्या श्रीवास्तव ने अपने समूह के साथ कथक शैली की नाटिका गंगा एक संकल्प की प्रस्तुति से गंगा की मनोव्यथा की अभिव्यक्ति की। इस नाटिका में कथक नर्तक अमित कुमार ने शिव तांडव के साथ गंगा को जटा में धारण करने के दृश्य को अपनी भाव-भंगिमाओं से जीवंत कर दिया।

नोट :

- वहीं, कथक नर्तक राजा कुमार ने काल्पनिक पात्र 'कालिमा'को अभिनीत कर अच्छा प्रदर्शन किया। यह नाटक गंगा को भगीरथ की आशा का संदेश देने के साथ संपन्न हुआ।
- इस अवसर पर नदियों के आध्यात्मिक, भौगोलिक और पौराणिक कथाओं पर आधारित सप्त तरंगिणी नृत्य संरचना की प्रस्तुति हुई। इस प्रस्तुति में रविशंकर, शालिनी महाराज, खुशी गुप्ता, हर्षिता विक्रम, संजना, स्नेहा, मुस्कान, सलोनी, रूपा, वंदिता व तनु ने नदियों के प्रवाह को भाव भंगिमाओं से दर्शाया।
- इस अवसर पर संजीव कपूर, तेजपाल सिंह ढिल्लन, सर्वेश राय, सरोज मिश्रा अमरेश पांडेय व अंजनी कुमार ने कला, चिकित्सा शिक्षा व अन्य क्षेत्रों के चर्चित हस्तियों को स्मृति चिह्न व अंगवस्त्र प्रदान कर सम्मानित किया गया।

बिहार में धान के नई किस्म सबौर कुंवर की खोज

चर्चा में क्यों ?

हाल हीं में बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर (भागलपुर) के वैज्ञानिकों ने धान की नई किस्म सबौर कुंवर की खोज की है।

प्रमुख बिंदु

- कम पानी, 25 प्रतिशत तक कम खाद और 110 से 115 दिनों में तैयार होने वाली धान की इस नई किस्म की खोज अनियमित और कम बारिश से परेशान धान उत्पादक किसानों के लिये लाभकारी है।
- धान की इस किस्म का औसत उत्पादन 55 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, जबकि अधिकतम उत्पादन 87 क्विंटल तक है।
- इसमें पौधे की लंबाई 100 से 105 सेंटीमीटर तक होती है। यह किस्म जीवाणु झुलसा, अंगमारी, झोंका एवं कंडुआ रोग प्रतिरोधी है। तना छेदक, भूरा कीट और पत्तीलपेटक के प्रति सहनशील है।
- इससे बिहार के मध्य और दक्षिण बिहार के ज़िलों बक्सर, रोहतास, भोजपुर, औरंगाबाद, लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर, भागलपुर, बांका आदि के किसानों को विशेष फायदा होगा।

डॉ. देवेंद्र कुमार शुक्ला बने बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नए अध्यक्ष

चर्चा में क्यों ?

9 मई, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार में भारतीय वन सेवा के पूर्व सेवानिवृत्त अधिकारी डॉ. देवेंद्र कुमार शुक्ला को बिहार सरकार ने 'बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड' का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- उल्लेखनीय है कि बिहार सरकार ने हाल ही में एक अधिसूचना के माध्यम से बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का पुनर्गठन किया है।
- डॉ. देवेंद्र कुमार शुक्ला ने बोर्ड के निवर्तमान अध्यक्ष डॉ. अशोक कुमार घोष का स्थान लिया है, जो हाल हीं में सेवानिवृत्त हो गए।
- इस पद पर नियुक्त होने के पूर्व डॉ. देवेंद्र कुमार शुक्ला बिहार राज्य जैव-विविधता बोर्ड के अध्यक्ष पद पर रह चुके हैं।

मध्य प्रदेश की तर्ज पर बिहार में भी ज़मीन की रजिस्ट्री में अब आधार अनिवार्य

चर्चा में क्यों ?

10 मई, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में मध्य प्रदेश की तर्ज पर अब जमीन और मकान खरीदने-बेचने पर आधार ऑथेंटिकेशन अनिवार्य होगा। इसके संबंध में राज्य मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव के.के पाठक ने आदेश जारी किया है।

प्रमुख बिंदु

- राज्य में आधार ऑथेंटिकेशन अनिवार्य होने से संपत्तियों के बेनामी ट्रांजेक्शन पर रोक लगेगी। वहीं, खरीदार-विक्रेता की सही पहचान भी आधार नंबर ऑथेंटिकेशन से आसान हो जाएगी, जिससे फर्जीवाड़ा पर रोक लगेगी।

नोट :

- विदित है कि पहले फर्जी व्यक्ति को खड़ा करा ज़मीन रजिस्ट्री का जो मामला सामने आता रहता था, इस पर अब बिल्कुल ही रोक लग जाएगी।
- राज्य में रजिस्ट्री ऑफिस में बिना काम जो भीड़ होती है। आधार ऑथेंटिकेशन अनिवार्य होने से इसमें भी कमी आएगी।
- विभागीय स्तर से जारी निर्देश के बाद अब ज़मीन रजिस्ट्री के दौरान खरीदार व विक्रेता के साथ गवाह व पहचान की जो आवश्यकता पड़ती थी, वह भी अब खत्म हो जाएगी। आधार ऑथेंटिकेशन से ही गवाह व पहचान की प्रक्रिया रजिस्ट्री ऑफिस पूरी करेगा।

बिहार के सारण में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन

चर्चा में क्यों ?

14 मई, 2023 को बिहार के सारण (छपरा) ज़िले में दो दिवसीय इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल सीजन 3 का समापन हो गया।

प्रमुख बिंदु

- छपरा के ऑडिटोरियम में 13 मई को शुरु हुआ दो दिवसीय फिल्म फेस्टिवल में देश के विभिन्न भाषाओं सहित विश्व के 21 देशों की फिल्मों का प्रदर्शन किया गया। इसके साथ ही फिल्म और नाटक के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाने वाले युवाओं को इससे जुड़ी जानकारी दी गई।
- इस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में फिलिपींस, इटली, तुर्की, भारत, स्पेन, अमेरिका, आस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान की फिल्में डॉक्यूमेंट्री और शॉर्ट फिल्मों का प्रदर्शन किया गया।
- साथ ही छोटे और स्कूली बच्चों के लिये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों को प्रदर्शित किया गया।
- इसके अलावा बहुत से सामाजिक मुद्दों पर बनाई गई डॉक्यूमेंट्री को भी दिखाया गया।
- सारण अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में भारत की दो फिल्मों ने अलग-अलग वर्गों में बेस्ट फिल्म अवार्ड जीता।
- बाल फिल्म इंस्पेशन ऑफ परसुइट और शॉट फिक्शन फिल्म वाशिंग मशीन को नेशनल वर्ग में बेस्ट फिल्म का खिताब दिया गया।
- वहीं अंतर्राष्ट्रीय कैटेगरी में तुर्की की फिल्म इक्रॉन एंड युशू को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री - इंटरनेशनल अवार्ड दिया गया।
- उल्लेखनीय है कि मयूर कला केंद्र के तत्वावधान व युवा कला व खेल मंत्रालय के सौजन्य से आयोजित दो दिवसीय फिल्म फेस्टिवल के दूसरे दिन करीब डेढ़ दर्जन फिल्में दिखाई गईं। उसके बाद ज्यूरी ने परिणामों की घोषणा की।
- वहीं पैनल डिस्कशन में देश-विदेश से आए कलाकरों ने लोगों के साथ अपना अनुभव साझा करते हुए नाटक साहित्य और सिनेमा के बारे में जानकारी दी।
- विदित कि सारण इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल बिहार का पहला और एकमात्र इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है।

नोट :

मजदूर के बेटे का कैलिफोर्निया में 2023 हैनसेन लीडरशिप प्रोग्राम के लिये चयन

चर्चा में क्यों ?

15 मई, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार बिहार के मसौढ़ी के एक दिहाड़ी मजदूर के 20 वर्षीय बेटे गौतम कुमार को अमेरिका के कैलिफोर्निया में 2023 हैनसेन लीडरशिप प्रोग्राम के लिये दुनिया के 20 युवाओं में चुना गया है।

प्रमुख बिंदु

- विदित है कि 20 वर्षीय गौतम कुमार फोर्ब्स 30 अंडर 30 सूची में रहे दुनिया के जाने-माने सामाजिक उद्यमी शरद विवेक सागर की संस्था डेक्सटेरिटी ग्लोबल से जुड़ा हुआ है।
- गौतम का परिवार गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) श्रेणी में आता है और इस विश्वस्तरीय प्रतिष्ठित महीने भर चलने वाले नेतृत्व कार्यक्रम के लिये चुने गए वह एकमात्र भारतीय हैं।
- गौतम के पिता संजय मांझी बिहार के मसौढ़ी में दिहाड़ी मजदूर और टोला सेवक के रूप में काम करते हैं। उनकी माँ लगनी देवी गृहिणी हैं। गौतम अपने परिवार में हाई स्कूल पूरा करने और कॉलेज जाने वाले पहले सदस्य हैं।
- गौतम को राष्ट्रीय संगठन डेक्स्टेरिटी ग्लोबल द्वारा पहचाना गया और तब से उन्हें डेक्स्टेरिटी द्वारा निरंतर प्रशिक्षित किया गया है। गौतम ने डेक्सटेरिटी ग्लोबल के नेतृत्व विकास कार्यक्रम डेक्सस्कूल और करियर विकास कार्यक्रम डेक्सटेरिटी टू कॉलेज में कठोर प्रशिक्षण प्राप्त किया।
- डेक्सटेरिटी ग्लोबल एक राष्ट्रीय संगठन है जो शैक्षणिक अवसरों और प्रशिक्षण के माध्यम से भारत एवं विश्व के लिये नेतृत्व की अगली पीढ़ी तैयार करने में कार्यरत है।
- दो वर्ष पूर्व गौतम राष्ट्रीय समाचारों में थे जब उनका डेक्सटेरिटी टू कॉलेज फेलो के रूप में पूर्ण छात्रवृत्ति पर अशोका विश्वविद्यालय में चयन हुआ था। वह वर्तमान में कंप्यूटर साइंस के द्वितीय वर्ष के छात्र है।
- गौरतलब है कि कैलिफोर्निया के यूनिवर्सिटी ऑफ सैन डिएगो में स्थित, हैनसेन लीडरशिप प्रोग्राम विश्व शांति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिये दुनिया भर के कुछ प्रेरणादायी युवाओं का चयन कर उन्हें प्रशिक्षित करता है।
- इस प्रोग्राम के अंतर्गत गौतम को पूर्ण छात्रवृत्ति मिली है जिससे उनके आने-जाने का हवाई किराया, रहने एवं खाने की व्यवस्था, स्थानीय परिवहन, स्वास्थ्य बीमा, वीजा शुल्क, आदि सहित पूरी लागत हैनसेन द्वारा उठाया जाएगा।

नोट :

बिहार में गंगा नदी के किनारे वाले शहरों में बनेगा एसटीपी

चर्चा में क्यों ?

21 मई, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में गंगा नदी के किनारे वाले शहरों में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) बनाया जाएगा। प्लांट से निकले वेस्ट से खाद तैयार किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- जानकारी के अनुसार बिहार में गंगा नदी के किनारे वाले 23 शहरों व इसकी सहायक नदियों वाले 16 शहरों में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) निर्माण के साथ ही 76 छोटे शहरों में एफएसटीपी (फिकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट) पर भी काम चल रहा है।
- इन एफएसटीपी के माध्यम से निजी सेप्टिक टैंकों से निकलने वाली गंदगी को एकत्रित करने के बाद उसे ट्रीट कर खाद तैयार किया जाएगा। फिलहाल चिह्नित निकायों में एफएसटीपी के निर्माण को लेकर ज़मीन की तलाश की जा रही है।
- 76 शहरों में लगाए जाने वाले एफएसटीपी प्लांटों की कुल क्षमता 1287 केएलडी होगी। यानि स्थापित होने वाले प्लांट हर दिन 1287 किलो लीटर सेप्टिक व दूषित कचरे का निबटारा कर सकेंगे।
- वर्तमान में छोटे शहरों में लोग मल त्याग के लिये सेप्टिक टैंक का ही प्रयोग करते हैं। निकायों के टैंकरों के माध्यम से इनको खाली कर निकलने वाली मलयुक्त गाद को खाली जगह, गड्ढा अथवा नालों में फेंक दिया जाता है, जिससे कई गंभीर रोग पैदा होने के साथ जल स्रोत दूषित होते हैं। इस पर लगाम लगाने और लोगों को सुविधा के लिये ही एफएसटीपी प्लांट स्थापित करने की योजना तैयार की गई है।
- अधिकारियों के मुताबिक यह प्लांट न केवल घरेलू सेप्टिक टैंकों के गाद को बल्कि शहर के अन्य सभी प्रकार के दूषित मलबे को ट्रीट कर सॉलिड और लिक्विड में अलग करता है। ट्रीटमेंट के बाद प्लांट के बचे सॉलिड वेस्ट का इस्तेमाल खाद के रूप में जबकि लिक्विड का इस्तेमाल सिंचाई के लिये किया जा सकता है। प्लांट पूरी तरह वैज्ञानिक आधार पर कई स्टेप में काम करता है।
- गंगा व सहायक नदियों के अलावा आठ अन्य महत्त्वपूर्ण शहरों में भी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) की तैयारी है। इनमें चार गंदी नदियों वाले शहर रामनगर, नरकटियागंज, रक्सौल और जोगबनी जबकि चार महत्त्वपूर्ण शहर गया, आरा, बेतिया और कटिहार हैं।
- यहाँ पर कुल 251.75 एमएलडी क्षमता का एसटीपी लगाया जा रहा है। इनमें से रामनगर में नौ एमएलडी और नरकटियागंज में सात एमएलडी क्षमता के एसटीपी को लेकर टेंडर प्रक्रिया चल रही है जबकि रक्सौल में 12 एमएलडी, जोगबनी में 4.25 एमएलडी, गया में 84 एमएलडी, आरा में 47 एमएलडी, बेतिया में 33 एमएलडी और कटिहार में 55.5 एमएलडी क्षमता के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का डीपीआर तैयार कर उसे एनएमसीजी (नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा) को भेजा गया है। इसकी मंजूरी मिलते ही टेंडर प्रक्रिया पूरी कर काम शुरू कर दिया जाएगा।
- गौरतलब है कि नदियों को स्वच्छ रखने को लेकर मंजूर की गई करीब छह दर्जन एसटीपी परियोजनाओं में अब तक मात्र सात परियोजनाओं को ही पूरा कर शुरू किया जा सका है। शहरों से निकलने वाले कुल गंदे पानी का दस फीसदी भी अब तक ट्रीट करने की सुविधा विकसित नहीं की जा सकी है।

नोट :

बिहार रजिस्ट्रीकरण नियमावली-2023 अधिसूचित

चर्चा में क्यों ?

22 मई, 2023 को बिहार के मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के सचिव सह निबंधन आयुक्त विनोद सिंह गुंजियाल ने बताया कि मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने कैबिनेट से मंजूर बिहार रजिस्ट्रीकरण नियमावली-2023 को अधिसूचित कर दिया है।

प्रमुख बिंदु

- अब सूबे के निबंधन कार्यालयों में विभाग द्वारा अनुमोदित मॉडल डीड के प्रारूप की टंकित प्रति पर ही दस्तावेज़ों का निबंधन स्वीकृत किया जाएगा। मॉडल डीड के माध्यम से पक्षकार द्वारा बिना किसी बाहरी सहयोग के दस्तावेज़ों का निबंधन कराया जा सकता है।
- निबंधन कार्यालयों ने एक अप्रैल 2023 से 20 मई, 2023 तक 82 लाख से अधिक दस्तावेज़ों की मॉडल डीड के माध्यम से रजिस्ट्री की है। आम जनों की सुविधा के लिये विभागीय वेबसाइट पर 25 प्रकार के मॉडल डीड का प्रारूप उपलब्ध है।
- विभागीय सचिव ने बताया कि 2023-24 के पहले 50 दिन में निबंधन कार्यालयों ने 853.82 करोड़ रुपए राजस्व की प्राप्ति की है। यह वार्षिक राजस्व लक्ष्य 6300 करोड़ रुपए का 13.55 फीसदी है। पिछले साल इस अवधि में करीब 800 करोड़ रुपए का राजस्व मिला था।

देश में CBDC का इस्तेमाल करने वाला पहला नगर निगम बना पटना

चर्चा में क्यों ?

23 मई, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार बिहार के पटना नगर निगम के महापौर, उप महापौर एवं नगर आयुक्त ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्मित डिजीटल करेंसी ई-रुपए का शुभारंभ किया, जिससे अब इस डिजीटल करेंसी का उपयोग संपूर्ण पटना नगर निगम क्षेत्र में किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- नगर निगम मुख्यालय मौर्यालोक परिसर में पूरी तरह से इस पेमेंट सिस्टम को अपनाया जाएगा। इसके साथ ही पटना नगर निगम के सभी अंचल एवं पेमेंट काउंटरों पर भी इसका उपयोग किया जाएगा।
- गौरतलब है कि भारत में सीबीडीसी (सेंट्रल बैंक डिजीटल करेंसी) इस्तेमाल करने वाला पहला नगर निगम पटना नगर निगम है। इस दौरान पार्षदों के लिये कार्यशाला का भी आयोजन किया गया, जहाँ उन्हें डिजीटल ई-रुपए के लाभ, इस्तेमाल की जानकारियाँ दी गईं।
- इस दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक के रिजनल हेड संजीव दयाल ने कहा कि यह एक बेहतर और सुरक्षित सिस्टम है, जहाँ पेमेंट करते ही तत्काल रूप से राशि क्रेडिट होती है। डिजीटली रूप से ट्रेंड होने पर आम नागरिकों को सुविधा मिलेगी। एक क्लिक में आसानी से पेमेंट किया जाएगा।
- नगर निगम आयुक्त अनिमेष कुमार पराशर ने कहा कि पटना नगर निगम के कार्यों को जनसुलभ बनाने एवं पेमेंट की प्रक्रिया को आसान करने के लिये लगातार प्रयास किया जा रहा है। नो कॉस्ट प्रोसेस के तहत ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम के माध्यम से पटना नगर निगम की आय बढ़ाने के साथ ही आम लोगों को घर बैठे सुविधाएँ मुहैया कराई जा रही हैं।
- उन्होंने बताया कि वर्तमान समय में पटना नगर निगम में ऑनलाइन भुगतान 30 प्रतिशत हो रहा है, इसे 90 से 95 प्रतिशत करना लक्ष्य है।
- उल्लेखनीय है कि सीबीडीसी एक डिजिटल मुद्रा है, लेकिन यह करेंसी निजी करेंसी से अलग है। पिछले एक दशक में क्रिप्टो करेंसी का बाज़ार तेज़ी से बढ़ा है। निजी डिजिटल मुद्राएँ किसी भी व्यक्ति की देनदारियों का प्रतिनिधित्व नहीं करती हैं, क्योंकि उनका कोई जारीकर्त्ता नहीं है।

नोट :

बिहार के हर पंचायत में लगेंगी फूड प्रोसेसिंग यूनिट

चर्चा में क्यों ?

22 मई, 2023 को बिहार उद्योग विभाग के निदेशक पंकज दीक्षित ने बताया कि राज्य की सभी 8387 पंचायतों में 'प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना' के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लगाने की योजना पर काम शुरू हो चुका है। उद्योग विभाग ने ज़िला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक को इसकी जिम्मेदारी सौंपी है।

प्रमुख बिंदु

- राज्य सरकार खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लगाने वाले उद्यमियों को हर तरह की सहायता देगी। उन्हें सब्सिडी से लेकर कर्ज तक की सुविधा मुहैया करायी जाएगी। इसके लिये ज़िला उद्योग केंद्र उद्यमियों का चयन और उनके प्रोजेक्ट का वेरिफिकेशन करेगा।
- इससे राज्य में कृषि आधारित उत्पादों का उपयोग खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में बड़े पैमाने पर होगा, साथ ही, स्वरोज़गार से प्रेरित होकर बेरोज़गार युवाओं को रोज़गार देने वाला बनाया जा सकेगा। खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा मिलने से आसपास के क्षेत्रों में होने वाले पलायन को रोका जा सकेगा।
- विभाग के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार इस कार्यक्रम में पीएम-एफएमई के तहत नये रोज़गार शुरू करने के लिये ऋण हेतु आवेदन भी लिये जाएंगे, ताकि इच्छुक आवेदकों को आर्थिक सहायता बैंक के माध्यम से उपलब्ध कराकर उन्हें नये उद्योग शुरू करने में सहायता की जा सके।
- साथ ही, मौजूदा इकाइयों को भी अपग्रेड करने के लिये अधिकतम 10 लाख रुपए प्रति यूनिट के साथ पात्र परियोजना लागत के 35 प्रतिशत पर क्रेडिट-लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
- इस योजना के माध्यम से केंद्र सरकार उन सभी लोगों की आर्थिक सहायता करेगी, जो लोग खाद्य उद्योग में अपना कोई नया काम शुरू करना चाहेंगे।

नोट :

बिहार के समीर पांडे ऑस्ट्रेलिया में मेयर पद हासिल करने वाले पहले भारतीय बने

चर्चा में क्यों ?

22 मई, 2023 को ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में सिटी ऑफ पैरामाटा काउंसिल ने भारतीय मूल (बिहार) के पार्षद समीर पांडेय को पैरामाटा शहर का लॉर्ड मेयर चुना है। समीर इस पद को हासिल करने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति हैं।

प्रमुख बिंदु

- समीर पांडेय का चुनाव भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑस्ट्रेलिया की यात्रा के साथ हुआ। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समीर पांडेय के पहले भारतीय मूल के रूप में मेयर चुने जाने की जानकारी दी।
- पैरामाटा न्यू साउथ वेल्स में सिडनी से सटा एक महत्त्वपूर्ण शहर है। पैरामाटा में भारतीय मूल के लोगों की संख्या काफी अधिक है और यह तेजी से बढ़ रही है। ढाई लाख से अधिक की आबादी वाले इस शहर में 11 फीसदी से भी अधिक लोग भारतीय मूल के हैं।
- करीब बीस साल पहले ऑस्ट्रेलिया पहुंचे समीर पांडेय आईटी विशेषज्ञ के साथ-साथ उद्योगपति हैं, जो एक इंजीनियर के रूप में ऑस्ट्रेलिया आये थे। वह लेबर पार्टी के सदस्य हैं और विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं, जिसमें वह बहुत मामूली अंतर से हारे थे।
- 2017 में वह पहली बार पार्षद का चुनाव जीते थे और 2022 में वह दूसरी बार पार्षद बने। 2022 में ही समीर काउंसिल के डिप्टी मेयर चुने गये थे।

'नेशनल वाटर अवार्ड 2022' में तीसरे स्थान पर रहा बिहार

चर्चा में क्यों ?

23 मई, 2023 को केंद्रीय जलशक्ति मंत्रालय द्वारा नेशनल वाटर अवाड्र्स 2022 में सर्वोत्तम राज्य की श्रेणी में बिहार को देश में तीसरे स्थान पर रखा गया है।

प्रमुख बिंदु

- बिहार सरकार द्वारा जल संरक्षण एवं जल संसाधनों के प्रबंधन के क्षेत्र में किये गए उत्तम कार्यों एवं प्रयासों को इस पुरस्कार के जरिये राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया है।
- जल संसाधन तथा सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री संजय कुमार झा ने कहा कि जल और हरियाली का संरक्षण एवं संवर्धन के लिये 'जल-जीवन-हरियाली अभियान' शुरू किया गया है। इस अभियान को संयुक्त राष्ट्र में भी सराहा गया है।
- सात निश्चय दो में घोषित अतिमहत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम को धरातल पर उतारने के लिये तत्परता से कार्य किये जा रहे हैं।

नोट :

- सात निश्चय दो में घोषित अतिमहत्त्वाकांक्षी कार्यक्रमों के अंतर्गत होने वाले कार्य:
  - गरौल वीयर सिंचाई योजना, दरभंगा- यह पुरानी कमला नदी पर वीयर सिंचाई योजना है, जिसमें हेड रेगुलेटर के माध्यम से सिंचाई सुविधा मिली है।
  - जैतपुरा पंप नहर योजना, भभुआ- इसके माध्यम से कर्मनाशा नदी के जलस्राव को विभिन्न प्रखंडों में सिंचाई सुविधा के लिये उपलब्ध कराई जाएगी।
  - गया ज़िले के बोधगया प्रखंड में मोहाने नदी पर बतसपुर वीयर का निर्माण एवं मोराटाल पईन से निस्सृत वितरण प्रणालियों का आधुनिकीकरण कार्य।
  - उदेरास्थान बराज योजना, बिहारशरीफ- यह एक वृहद सिंचाई योजना है, जिससे जहानाबाद एवं गया ज़िले के कई प्रखंडों में सिंचाई क्षमता विकसित हुई है।
  - बिहुल वीयर सिंचाई योजना, मधुबनी- लक्ष्मीपुर ग्राम के निकट बिहुल नदी पर गेटेड वीयर, उसके अपस्ट्रीम में दाईं एवं बायीं तरफ एफलक्स बांध तथा डाउनस्ट्रीम में दोनों तरफ गाइड बांध का निर्माण एवं सुरक्षात्मक कार्य होने हैं। इसमें दाएँ मुख्य नहर से निस्सृत नहर प्रणाली की कुल लंबाई 3.35 किमी. है तथा बाएँ मुख्य नहर से निस्सृत नहर प्रणाली की लंबाई 6.33 किमी. है।
  - मलई बराज योजना के अंतर्गत रोहतास ज़िले के दावथ प्रखंड में कोंद नदी पर बराज का निर्माण कर लिंक नहर के माध्यम से बक्सर ज़िले में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
  - बलवाघाट बराज-सह-सिंचाई योजना, मधुबनी- बलवा ग्राम के पास धौंस नदी पर आधारित इस सिंचाई योजना में दो हेड रेगुलेटर (दायाँ एवं बायाँ) के अलावा जर्जर पड़ी उपवितरणी का जीर्णोद्धार कार्य (9.27 किमी.) और दाईं तरफ मौजूद पईन के रूपांकित जलस्राव के अनुरूप पुनर्स्थापन कार्य (13.36 किमी.) किया गया है।
- विदित है कि पहला राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2018 में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था।
- राष्ट्रीय जल पुरस्कारों ने जल संसाधन को लेकर स्टार्ट-अप के साथ-साथ अग्रणी संगठनों को नीति-निर्माताओं के साथ जुड़ने और विचार-विमर्श करने का बेहतर अवसर प्रदान किया है कि कैसे बेहतरीन तरीके से जल संसाधन प्रबंधन के नए और सही तरीकों को अपनाया जाए।
- इस बार मध्य प्रदेश ने सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में शीर्ष स्थान हासिल किया है। इसके बाद ओडिशा ने दूसरा स्थान जबकि आंध्र प्रदेश और बिहार को तीसरे स्थान के लिये संयुक्त विजेता घोषित किया गया है।

नोट :

बिहार में 793.97 करोड़ रुपए के 67 निवेश प्रस्तावों को मिली पहली मंजूरी

चर्चा में क्यों ?

25 मई, 2023 को बिहार विकास आयुक्त विवेक कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित राज्य निवेश प्रोत्साहन परिषद की 47वीं बैठक में दो करोड़ रुपए से अधिक के 67 प्रस्तावों को प्रथम स्टेज की हरी झंडी दी गई है। इनमें 793.97 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावित किये गए हैं।

प्रमुख बिंदु

- उद्योग विभाग की तरफ से जारी की गई आधिकारिक जानकारी के मुताबिक सर्वाधिक 18 प्रस्ताव खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में हैं। इसमें कुल निवेश 435 करोड़ रुपए से अधिक के प्रस्तावित किये गए हैं।
- इसके अलावा राइस मिल के 18 प्रस्तावों में 104.75 करोड़ रुपए के प्रस्ताव, जनरल मैन्युफैक्चरिंग के 11 प्रस्तावों में 62.48 करोड़ रुपए, टैक्सटाइल सेक्टर के छह प्रस्तावों में 42.64 करोड़ रुपए, टूरिज्म सेक्टर के चार प्रस्तावों में 62.99 करोड़ रुपए, प्लास्टिक एंड रबर सेक्टर के चार प्रस्तावों में 41.97 करोड़ रुपए और शेष छह प्रस्ताव में 43.78 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई है।
- सबसे अहम निवेश प्रस्ताव :
  - किशनगंज के ठाकुरगंज का मक्का आधारित दो यूनिट प्रस्तावित हैं। इसमें 238 करोड़ रुपए और 92 करोड़ का निवेश संभावित।
  - मुजफ्फरपुर में अमूल मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट में 25.57 करोड़ रुपए निवेश प्रस्तावित।
  - गया में टैक्सटाइल यूनिट में 36.88 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित।
  - मोतिहारी में रिसार्ट एंड होटल में 38.27 करोड़ रुपए का निवेश।
  - सीवान के दाउद नगर में होटल निर्माण में 14.53 करोड़ रुपए का निवेश।
  - पटना में प्लास्टिक एवं रबर सेक्टर की दो यूनिटों में 32 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित।
  - गया में हेल्थ केयर सेक्टर में 19.93 करोड़ रुपए का निवेश संभव।
  - भोजपुर में एयर कूलर निर्माण यूनिट में 11 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्ताव।
- इसके अलावा दो करोड़ से कम के 51 निवेश प्रस्तावों पर सहमति दी गई है। इसमें कुल 52.49 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावित हैं।
- खाद्य प्रसंस्करण के 20 प्रस्तावों में 20.54 करोड़, एक राइस मिल में 84.50 लाख, जनरल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के नौ प्रस्तावों में 11.12 करोड़, प्लास्टिक एवं रबर के नौ प्रस्तावों में 6.93 करोड़, टैक्सटाइल सेक्टर के 4.97 करोड़, स्मॉल मशीन मैन्युफैक्चरिंग के दो प्रस्तावों में 89 लाख, आइटी एंड आइटीइएस के दो प्रस्तावों में 2.24 करोड़ और हैल्थ केयर के तीन प्रस्तावों में 2.64 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावित किये गए हैं।

नोट :

बिहार शिक्षा विभाग और चार NGO के मध्य होगा एमओयू

चर्चा में क्यों ?

28 मई, 2023 को बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई विशेष बैठक में निर्णय लिया गया है कि राज्य के सरकारी स्कूलों की शिक्षा की गुणवत्ता और विस्तार के लिये चार स्वयंसेवी संस्थाएँ वित्तीय और तकनीकी मदद मुहैया कराने के लिये शिक्षा विभाग के साथ एमओयू करने जा रही हैं।

प्रमुख बिंदु

- इनमें केंद्रीय भंडार नामक संस्था कक्षा 9 और 10 के विद्यार्थियों को स्पेशल कंटेंट मुहैया कराएगी, विशेष रूप से क्यूआर कोड से क्रियाशील होने वाली विषय सामग्री उपलब्ध कराएगी।
- इसके अलावा तीन अन्य संस्थाओं ने बिहार में शिक्षा की बेहतरी के लिये काम करने की इच्छा व्यक्त की है, जिनमें आदित्य बिड़ला ग्रुप की संस्था माइंड स्पार्क भी शामिल है, जो एप के माध्यम से बच्चों का लर्निंग लेवल सुधारने पर काम करने जा रही है।
- केंद्रीय भंडार संस्था लर्निंग एप के जरिये विद्यार्थियों एवं अध्यापकों को मोबाइल एप और पोर्टल के जरिये पठन-पाठन सामग्री उपलब्ध कराएगी। एप राज्य सरकार के सुझाए गए नाम से लॉन्च किया जाएगा। इस पर आने वाला खर्च राज्य सरकार वहन करेगी।
- इसी तरह माइंड स्पार्क को निर्देशित किया गया कि पटना ज़िले के जिन कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध हैं, उन विद्यालयों में कार्य करने को लेकर एमओयू लेकर आए। यह संस्था सीखने के स्तर पर कक्षा के अनुरूप करने में सहयोग प्रदान करती है।
- बैठक की रिपोर्ट के मुताबिक बच्चों के नैतिक और आध्यात्मिक विकास के लिये जेसुइट पीस मिशन काम करेगी। खासतौर पर बोधगया प्रखंड की दो पंचायत इलराह और शेखवारा पंचायत के 13 विद्यालयों में मेडिटेशन और विज़डम ऑफ फॉर ऑल रिलीजियस का प्रशिक्षण दी जाएगी ।
- जेसुइट पीस मिशन के तहत यह काम बोधगया के जीवन संघम करेगा, जो कि पटना जेसुइट सोयाइटी की चैरिटेबल संस्था है।
- इसी तरह एजुकेट इंडिया नाम की संस्था कक्षा तीन से पाँच तक के विद्यार्थियों को प्रारंभिक साक्षरता मुहैया कराएगी। इसके लिये डोर-टू-डोर सर्वेक्षण किया जाएगा। दो से तीन ज़िलों मंल हेल्प डेस्क भी बनाना प्रस्तावित है। बैठक में एजुकेट इंडिया को निर्देशित किया गया कि एमओयू का ड्रॉफ्ट तैयार करे, इसके बाद उसके प्रस्ताव पर निर्णय लिया जाएगा।

बिहार के सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों के भवन एक ही रंग के होंगे

चर्चा में क्यों ?

30 मई, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार बिहार स्वास्थ्य विभाग ने 'मिशन परिवर्तन' के तहत राज्य के सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों के भवनों को एक समान रंग में रंग-रोगन करने का निर्देश दिया है। इसका मॉडल भगवान महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान, पावापुरी (बिम्स) को माना गया है।

प्रमुख बिंदु

- विदित है कि बिहार के मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में 'मिशन परिवर्तन'चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य है कि राज्य के सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों को चकाचक बनाया जाए।
- साफ-सफाई के साथ विभाग की कोशिश है कि सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों के लुक भी एक समान हो। किसी भी मरीज को मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में आते समय दूर से ही रंग के आधार पर आसानी से पहचान हो जाए।
- स्वास्थ्य विभाग ने 'मिशन परिवर्तन' के तहत राज्य के सभी 10 मेडिकल कॉलेज अस्पतालों- पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल, श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल, मुजफ्फरपुर, जीएमसी, बेतिया, दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल, जेएलएनएमसीएचभागलपुर, जीएमसी, पूर्णिया, जेएनकेटीएमसीएच, मधेपुरा और एएनएमसीएच, गया के भवनों को एक समान रंग में रंग-रोगन करने का निर्देश दिया है।

नोट :

- इसका मॉडल भगवान महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान पावापुरी (बिम्स) को माना गया है। अब बिम्स के भवनों के रंग जैसा ही सभी मेडिकल कॉलेजों के भवनों की रँगाई पुताई की जाएगी।
- गौरतलब है कि इसके पहले 'मिशन 60 डे' के तहत राज्य के सभी ज़िला अस्पतालों को भी एक तरह के रंग में रंगने का आदेश दिया गया था। राज्य के सभी ज़िला अस्पतालों के भवनों को एक रंग में रँगाई कर दिया गया है। इसी फार्मूले को बढ़ाते हुए अब मेडिकल कॉलेजों के भवनों और वार्डों को एक समान रंग में करने का निर्देश दिया गया है।
- इसी प्रकार सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों को निर्देश दिया गया है कि पुराने भवनों को जिनका अब उपयोग नहीं किया जा सकता है, उनकी पहचान कर ली जाए। साथ ही वैसे भवनों को बीएमएसआइसीएल के माध्यम से जमींदोज कराने की कार्रवाई की जाए।

दृष्टि The Vision

नोट :